

रायपुर में सुशासन सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रायपुर में **सुशासन** पर दो दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के तहत शुरू किये गए शासन सुधारों में "**ईज़ ऑफ लविंग**" और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है ।

प्रमुख बंदि

- कार्यक्रम वविरण:
 - प्रशासनिक सुधार एवं शकियत नविरण वविण (DARPG) और छत्तीसगढ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजति कयि गय।
 - सार्वजनिक सेवा वविरण सुधारों पर चर्चा करने के लयि नीति निर्माताओं, नौकरशाहों और वशिषज्जों को एक साथ लया गय।
- वकिंदरीकृत शासन पर चर्चा:
 - शासन संबंधी चर्चाओं को सतता के केंद्रीय ककर्षों से आगे ले जाने के महत्त्व पर बल दयि गय।
 - राज्यों में आयोजति सम्मेलनों से कषेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान सुनिश्चति होते हैं तथा केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढावा मलिता है।
 - इसी प्रकार के कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमलिनाडु तथा अन्य राज्यों में भी आयोजति कयि गए, जो राष्ट्रव्यापी पहुँच को दर्शाते हैं।
- ऐतहिसकि प्रशासनिक सुधार:
 - नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करने के लयि 2,000 से अधिक अप्रचलति नियमों को हटा दयि गय है।
 - सत्यापति दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करके प्रशासनिक प्रक्रयिओं को सरल बनाय गय, जसिसे नागरकिों में वशिवास मज़बूत हुआ।
 - पेंशनभोगयिों के लयि चेहरा पहचानने वाली तकनीक शुरू की गई, जसिसे भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो गई।
 - समय पर भुगतान के लयि पेंशन और परिवार पात्रता प्रणालयिों का डजिटलीकरण बढाया गय।
 - गुरुप B और C के पदों के लयि साक्षात्कार समाप्त कर दयि गय, जसिसे भर्ती प्रक्रयिओं में पक्षपात और भ्रष्टाचार कम हो गय।
- सुधारों का प्रभाव:
 - शासन सुधारों का उद्देश्य वलिंब को कम करना, भ्रष्टाचार से नपिटना और नागरकिों के लयि प्रशासनिक प्रक्रयिओं को सरल बनाना है।
 - कार्यकुशलता बढाने के लयि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाय गय, जसिसे वशिष रूप से वरषिठ नागरकिों और ग्रामीण आबादी को लाभ मलि।

सुशासन



विश्व बैंक के अनुसार, सुशासन वह माध्यम है जिसके द्वारा विकास के लिये किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

संदर्भ

- भगवद् गीता
- कौटिल्य का अर्थशास्त्र: राजा की भूमिका में प्रजा का कल्याण सर्वोपरि माना जाता है
- महात्मा गांधी ने "सु-राज" (सुशासन) पर ज़ोर दिया है
- सतत विकास लक्ष्य 16: शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकार और सुरक्षा में सुधार

मुख्य विशेषताएँ (मानवाधिकार परिषद् के अनुसार)

- ⌚ पारदर्शिता
- ⌚ ज़िम्मेदारी
- ⌚ जवाबदेहिता (Responsibility)
- ⌚ भाग लेना (Participation)
- ⌚ जवाबदेही (Responsiveness) [लोगों की आवश्यकताओं के प्रति]

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिये गए 8 सिद्धांत



भारत में सुशासन नामक पहल

राष्ट्रीय सुशासन दिवस: 25 दिसंबर (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से)

■ पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता

- ⌚ सूचना का अधिकार (अनुच्छेद 19 (1)) और RTI अधिनियम, 2005
- ⌚ ई-गवर्नेंस (न्यूनतम सरकार - अधिकतम गवर्नेंस); डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
- ⌚ केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)

■ विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन

- ⌚ नीति आयोग (सहकारी संघवाद)
- ⌚ 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन

■ नागरिक भागीदारी और सशक्तीकरण

- ⌚ मेक इन इंडिया पहल, MyGov प्लेटफॉर्म, RTE अधिनियम, 2009

■ वैधानिक सुधार

- ⌚ मॉडल पुलिस अधिनियम (2015), e-FIR, e-कोर्ट प्रोजेक्ट, SUPACE पोर्टल

■ सुशासन सूचकांक (इसे DARPG द्वारा तैयार किया जाता है)

संबंधित चुनौतियाँ

- ⌚ भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2023 में भारत 93/180वें स्थान पर है
- ⌚ असमानता और सामाजिक बहिष्कार: भारत में धन की असमानता 60 वर्ष के उच्चतम स्तर पर है (वर्ष 2024 में) (शीर्ष 1% लोगों के पास 40.1% संपत्ति है)
- ⌚ अपर्याप्त न्यायिक अवसंरचना: विभिन्न न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, (मात्र उच्चतम न्यायालय में ~80,000)

सुझाव

- ⌚ नीतिगत निर्णयों में नागरिकों को शामिल करने के लिये एक सुरक्षित डेटा प्लेटफॉर्म निर्माण की आवश्यकता है
- ⌚ AI-संचालित शिकायत निवारण
- ⌚ सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Model): सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिये

